Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 8

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

RAS

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

क्र.सं.	अध्याय नाम	पृष्ठ सं.
1.	राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य	1
2.	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	5
3.	ग्रामीण विकास और पंचायती राज	20
4.	औद्योगिक विकास	29
5.	आधारभूत संरचना और संसाधन	42
6.	सेवा क्षेत्र	49
7.	राजस्थान में शहरी विकास	58
8.	राजस्थान की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं	67
9.	अन्य सामाजिक क्षेत्र योजना/कार्यक्रम	79
10.	राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन	91
11.	सतत विकास लक्ष्य- राजस्थान में मुद्दे और चुनौतियाँ	97

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

प्रश्न 1 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए: (2023)

(i) यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती हैं।

(ii) पंजीकरण के बाद, पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोज़गार उपलब्ध करवाया जाता है।

(1) न तो (i) न ही (ii) सही है ।
(2) (i) व (ii) दोनों सही है ।
(3) केवल (ii) सही है।
(4) केवल (i) सही है ।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 2 निम्नांकित में से कौन सा विकल्प (इंदिरा महिला) शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है ? (2023)

(1) महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना ।
(2) मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबन्धन के बारे में जागरूकता पैदा करना ।
(3) महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ।
(4) बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार ।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 3 चुकन्दर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था । (2023)

(1) श्री गंगानगर में
(2) भोपालसागर में
(3) केशोरायपाटन में
(4) उदयपुर में
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 4 निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वॉटर सिवरेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है ? (2023)

(1) राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(2) राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(3) राजस्थान हाउसिंग बोर्ड
(4) राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 5 निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है - "कोई भूखा न सोए" ? (2023)

(1) 'बालगोपाल योजना
(2) इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना
(3) अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
(4) इंदिरा रसोई योजना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 6 वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है ? (2023)

(1) 6.54 प्रतिशत
(2) 5.18 प्रतिशत
(3) 4.86 प्रतिशत
(4) 3.78 प्रतिशत
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 7 राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है ? (2023)

(1) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

(2) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

(3) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

(4) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 8 वर्ष 2022-23 में, राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा ? (2023)

(1) परिवहन, भण्डारण एवं संचार

(2) व्यापार, होटल एवं जलपान गृह

(3) स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएँ

(4) वित्तीय सेवाएँ

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 9 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA (स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर) में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है ? (2023)

(1) इनमें से कोई नहीं (2) सेवा क्षेत्र

(3) उद्योग क्षेत्र (4) कृषि क्षेत्र

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 10 राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-II परियोजना के अन्तर्गत 801 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है ? (2023)

(1) नाबार्ड (2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(3) विश्व बैंक (4) एशियन विकास बैंक

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 11 राजस्थान में किस एजेंसी को पी.एम. - कुसुम योजना (कम्पोनेंट A) के क्रियान्वयन के जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावॉट से 2 मेगावॉट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने हैं ? (2023)

(1) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिऐंसी (2) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

(3) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (4) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 12 राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया ? (2023)

(1) 2008 (2) 2005

(3) 2003 (4) 2001

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है ? (2023)

(1) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)

(2) महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना (एम.जी.जे.बी.वाय.)

(3) डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(4) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाय.)

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 14 राजस्थान में अटल भू-जल योजना के लिये निम्न में से कौन सा/से कथन सही है/हैं ? (2023)

(a) अटल भू-जल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है ।

(b) इस योजना का फोकस भू-जल प्रबन्धन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है।

नीचे दिये गये कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिये :

(1) न तो (a) न ही (b) (2) केवल (b)

(3) केवल (a) (4) (a) और (b) दोनों

(5) अनुत्तरित प्रश्न

विश्लेषण- RPSC का रुझान बताता है कि RAS परीक्षा में प्रतिवर्ष राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सामान्यतः सरल और तथ्यात्मक होते हैं, जिन्हें सही तथ्यों की जानकारी से आसानी से हल किया जा सकता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के व्यापक दृष्टिकोण जैसे स्थिर और चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), भारतीय अर्थव्यवस्था में GSDP का हिस्सा, तथा स्थिर और चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा, कमजोर वर्गों जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और प्रौढ़ जनसंख्या पर आधारित प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस संदर्भ में प्रमुख(flagships) और हाल ही में शुरू की गई योजनाएं अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती हैं, विशेषकर योजनाओं की शुरुआत की तारीख, उद्देश्य और लाभार्थियों से जुड़े तथ्य महत्वपूर्ण है।

आर्थिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे पर आधारित प्रश्न भी अंक बढ़ाने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, चालू और स्थिर कीमतों पर GSVA (Gross State Value Added) में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, किसी विशेष क्षेत्र में उप-क्षेत्रों का योगदान और उनकी विकास दर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर, पवन और बायोमास से जुड़े प्रश्न भी अक्सर देखने को मिलते हैं। बुनियादी ढांचे और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संदर्भ में, परियोजना की वित्तपोषण एजेंसी का नाम, उद्देश्य और कार्यान्वयन के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

इसके अलावा, प्रमुख नीतियां और उनके प्रावधान, वित्तीय संसाधन और FRBM अधिनियम, सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक और जिलों की रैंकिंग से जुड़े प्रश्न भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। बजट के संदर्भ में उत्कृष्टता केंद्र, विभिन्न संस्थानों के स्थान, और हाल ही में शुरू की गई योजनाओं के उद्देश्य और आदर्श वाक्य पर प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा की तैयारी में इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि अधिकतम अंक अर्जित किए जा सकें।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य

राजस्थान की रूपरेखा

राजस्थान जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि.मी. है, जो कि 10 संभागों और 50 जिलों में विभक्त है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है जो की सर्वाधिक है।

राज्य के प्रमुख संकेतकों का भारत से तुलनात्मक विवरण

संकेतक		
भौगोलिक क्षेत्र (लाख वर्ग किमी.)	32.87	3.42
जनसंख्या (करोड़, 2011)	121.09	6.85
दशकीय वृद्धि दर (2001-2011)	17.7 %	21.3 %
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी. जनसंख्या, 2011)	382	200
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या (2011)	31.2%	24.9%
अनुसूचित जाति की जनसंख्या (2011)	16.6%	17.8%
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (2011)	8.6%	13.5%
लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं, 2011)	943	928
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) (प्रति हजार पुरुष बच्चों पर महिला बच्चे, 2011)	919	888
साक्षरता दर (2011)	73.0%	66.1%
साक्षरता दर (पुरुष) (2011)	80.9%	79.2%
साक्षरता दर (महिला) (2011)	64.6%	52.1%
कार्य सहभागिता दर (2011)	39.8%	43.6%
अशोधित जन्म दर (प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या, 2020*)	19.5	23.5
अशोधित मृत्यु दर (प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या, 2020*)	6.0	5.6
शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म, 2020*)	28	32
मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति लाख जीवित जन्म, 2018-20*)	97	113
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्षों में , 2016-20*)	70.0	69.4

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी निश्चित समयावधि के दौरान राज्य में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का है।

स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष- 2011-12)

मूल्य ₹ लाख करोड़ में	173	8.45
वृद्धि दर	8.2%	8.03%

प्रचलित मूल्यों पर

मूल्य ₹ लाख करोड़ में	295	15.28
वृद्धि दर	9.6%	12.56%

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

NSDP = GSDP - स्थायी पूंजीगत उपभोग

	स्थिर मूल्यों पर (2011-12)	प्रचलित मूल्यों पर
मूल्य ₹ लाख करोड़ में	7.41	13.69
वृद्धि दर	8.10%	12.70%

सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

GSVA = जीएसडीपी – कर + सब्सिडी

इसका उपयोग राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान को दर्शाने के लिए किया जाता है

GSVA- प्रचलित मूल्यों पर

कृषि क्षेत्र	17.66%	26.72%
औद्योगिक क्षेत्र	27.62%	28.21%
सेवा क्षेत्र	54.72%	45.07%

स्थिर मूल्यों पर

	योगदान	वृद्धि
कृषि क्षेत्र	26.21%	2.13%
औद्योगिक क्षेत्र	29.84%	12.43%
सेवा क्षेत्र	43.95%	6.37%

प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है।

प्रति व्यक्ति आय = NSDP/राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या

प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय-

- वर्ष 2023-24 - ₹1,67,964 (अनुमानित)
- वर्ष 2022-23 - ₹1,50,653
- यह गत वर्ष 2022-23 की तुलना से 2023-24 में 11.49 % की वृद्धि दर्शाता है।

स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय-

- वर्ष 2023-24 - ₹90,831 (अनुमानित)
- वर्ष 2022-23 - ₹ 84,935
- यह गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 6.94 % की वृद्धि दर्शाता है।

सकल स्थाई पूंजी निर्माण (GFCF)

सकल स्थाई पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसम्पत्तियों में से निस्तारित सम्पत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसम्पत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है।

वर्तमान मूल्य पर (2022-23)

मूल्य: ₹ 3,99,594 करोड़ (GSDP का 29.43%)

विकास: 12.78% over 2021-22

GFCF में 3 सर्वाधिक योगदान देने वाले क्षेत्र

1. निर्माण
2. आवासीय भवन
3. लोक प्रशासन

GFCF में योगदान

निजी क्षेत्र- 78.54%

सार्वजानिक क्षेत्र- 21.46%

गत 5 वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वृद्धि उतार-चढ़ाव भरी रही

मूल्य सांख्यिकी

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

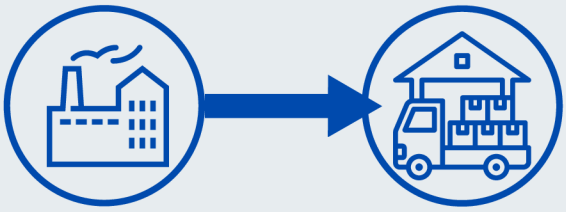

निर्माता → थोक विक्रेता

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

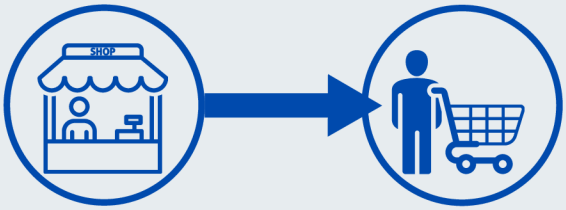

खुदरा विक्रेता → उपभोक्ता

मासिक आधार पर गणना की गई कीमतों में परिवर्तन

- विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है
- आधार वर्ष: 1999-2000
- अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा

राजस्थान का WPI

	संख्या	भार	वार्षिक वृद्धि
प्राथमिक वस्तुएं	75	33.894%	9.96% (Highest)
विनिर्मित उत्पाद	69	49.853%	0.23%
ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उप्स्नेहक	10	16.253%	0.39%

राजस्थान में CPI (IW) के 3 केंद्र

- खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व दिया जाता है

1 औद्योगिक कर्मचारी के लिए CPI (CPI-IW)

- श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा
- आधार वर्ष: 2016
- देश भर के 88 केंद्रों पर आधारित

2 कृषि मजदूरों के लिए CPI (CPI-AL)

- श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा
- आधार वर्ष: 1986-87

3 ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI (CPI-RL)

- श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा

4 ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए C.P.I. (CPI - R, U और C)

- N.S.O., नई दिल्ली द्वारा
- आधार वर्ष: 2012

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

राज्य में कृषि की स्थिति-
(अ) सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

विवरण	स्थिर मूल्यों पर	स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर	प्रचलित मूल्यों पर	प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर
GSDP में कृषि का हिस्सा	26.21%	2.13%	26.72%	9.64%
संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) (वर्ष 2019 - 20 से 2023 - 24 तक)	3.86%	-	9.99%	-

(ब) संबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रवार योगदान (प्रचलित मूल्यों पर):-

S.No.	क्षेत्र	योगदान	वृद्धि
1.	पशुधन	48.58 %	5.83%
2.	फसलें	44.53%	-1.61% (कमी)
3.	वानिकी एवं लॉगिंग	6.40%	2.82%
4.	मत्स्य	0.49%	15.21%

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2023-24 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) में योगदान

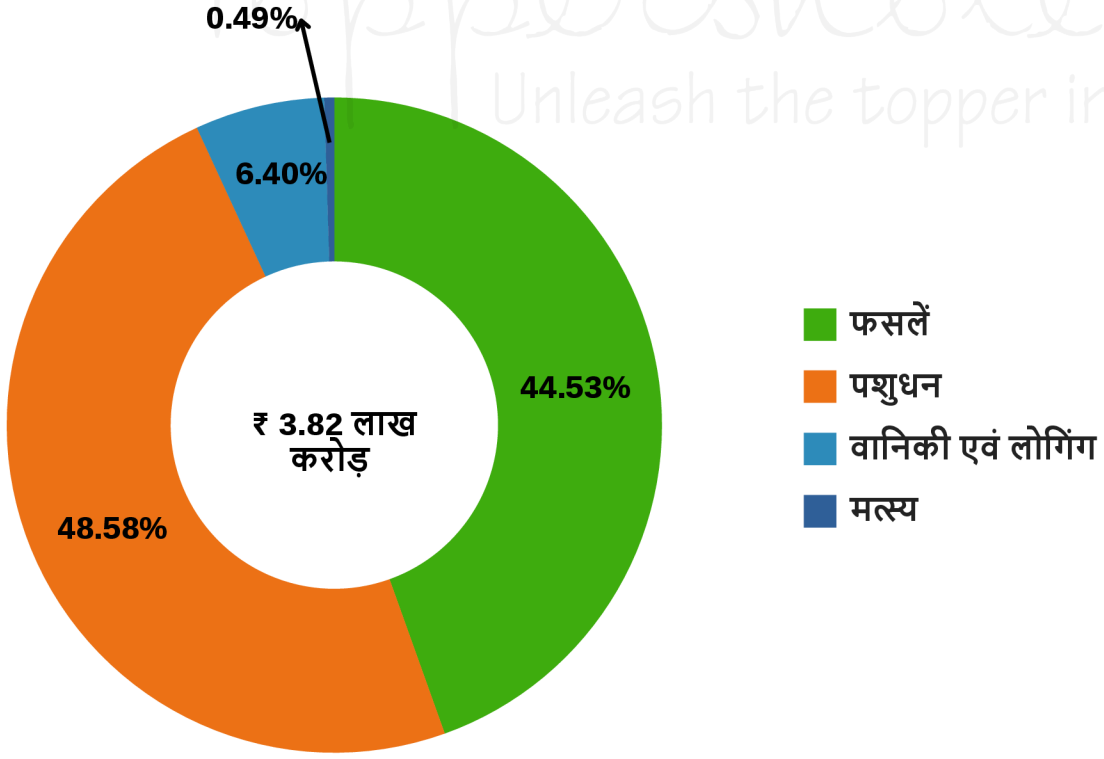

toppersnotes
Unleash the topper in you

भू-उपयोग

- राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल - 342.81 लाख हेक्टेयर।

S.No.	भूमि के प्रकार	प्रतिशत
1.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	53.74
2.	बंजर भूमि	10.39
3.	वानिकी	8.09
4.	ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि	6.89
5.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	5.92
6.	अन्य चालू पड़त भूमि	5.68
7.	स्थायी चारागाह भूमि	4.82
8.	चालू पड़त	4.38
9.	वृक्षों के झुण्ड और बाग	0.09

भू उपयोग सांख्यिकी 2022-23

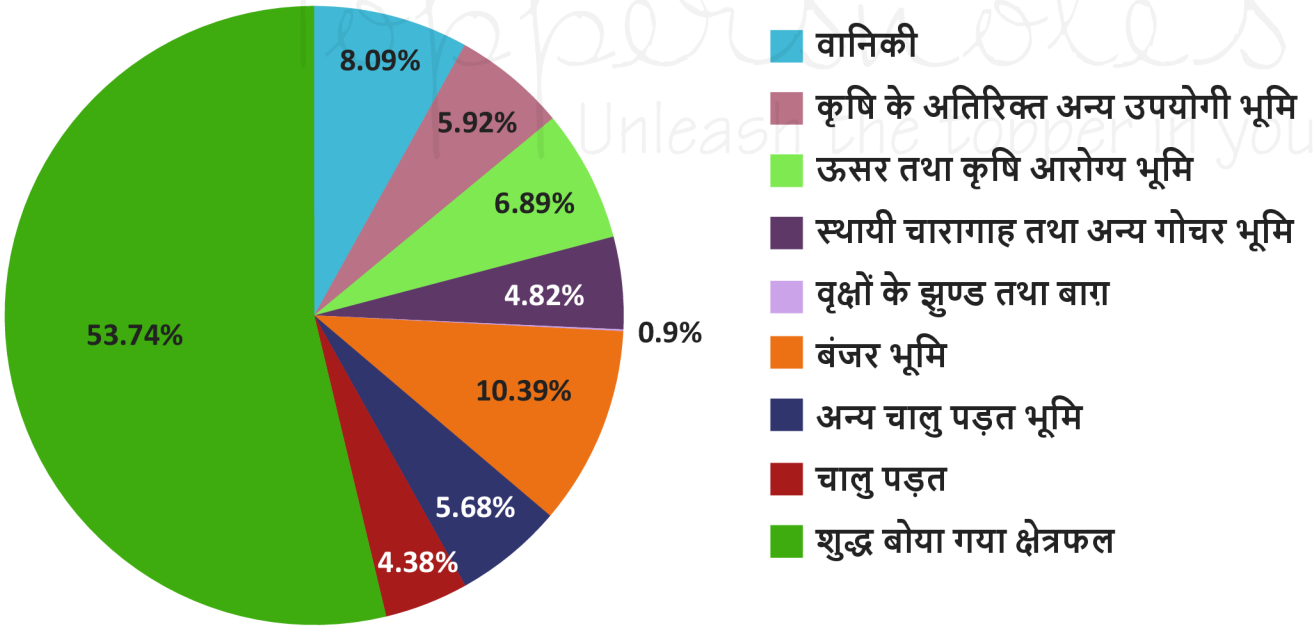

प्रचालित जोत धारक

	कृषि गणना (2015-16)	परिवर्तन (2010-11 से)
कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या	76.55 लाख	11.14% (वृद्धि)
कुल जोतों का क्षेत्रफल	208.73 लाख हेक्टेयर	1.24% (कमी)
भूमि जोतों का औसत आकार	2.73 हेक्टेयर	11.07 % (कमी)

महिला प्रचालित जोत धारक

	2015-16	2010-11
संख्या	7.75 लाख	41.94 % (वृद्धि)
क्षेत्र	16.55 लाख हेक्टेयर	24.44% (वृद्धि)

जोत धारक	आकार	परिवर्तन
सीमान्त (1.0 हैक्टेयर से कम)	40.12 %	19.79% (वृद्धि)
लघु (1.0-2.0 हैक्टेयर)	21.90 %	10.50% (वृद्धि)
अर्ध-मध्यम (2.0-4.0 हैक्टेयर)	18.50%	5.67% (वृद्धि)
मध्यम (4.0-10.0 हैक्टेयर)	14.79 %	13.20% (वृद्धि)
वृहद (10.0 हैक्टेयर एवं अधिक)	4.69 %	11.14 % (कमी) कारण – जोत के आकार में कमी

फसल उत्पादन	उत्पादन (लाख मीट्रिक टन में)	
	2023-24	परिवर्तन
खाद्यान्न उत्पादन	245.01 लाख मीट्रिक टन	3.08

	2023-24	परिवर्तन
खरीफ	89.83	18.04%
रबी	155.18	8.37%

	2023-24	परिवर्तन
अनाज	208.61	3.59%
दलहन	36.40	0.05%

	2023-24	परिवर्तन
तिलहन	101.24	2.10%

	2023-24	परिवर्तन
गन्ना	3.28	4.13%

	2023-24	परिवर्तन
कपास	26.21	5.58%

Toppersnotes Unleash the topper in you

क्र.सं.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान (प्रतिशत में)
1.	बाजरा	राजस्थान	उत्तरप्रदेश	38.98
2.	सरसों	राजस्थान	मध्यप्रदेश	46.63
3.	पोषक अनाज	कर्नाटक	राजस्थान	13.89
4.	कुल तिलहन	राजस्थान	मध्यप्रदेश	22.25
5.	कुल दलहन	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	14.51
6.	मूंगफली	गुजरात	राजस्थान	16.83
7.	चना	महाराष्ट्र	मध्यप्रदेश	19.28
8.	ज्वार	महाराष्ट्र	कर्नाटक	12.67
9.	सोयाबीन	महाराष्ट्र	मध्यप्रदेश	7.12
10.	ग्वार	राजस्थान	-	87.69 (अधिकतम)

कृषि से संबंधित योजनाएं

बीज

- **मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना:**
  - प्रारंभ: 2017
  - प्रारंभ में 3 कृषि-जलवायुवीय खण्डों (कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर) में क्रियान्वयन ।
  - वर्ष 2018-19 से राज्य के समस्त 10 कृषि-जलवायुवीय खण्डों में क्रियान्वयन किया गया। (सम्पूर्ण राजस्थान)
  - उद्देश्य: किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
  - इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सिंचाई

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2015

- नोडल विभाग- बागवानी विभाग।
- उद्देश्य: खेत तक पानी की पहुँच को बढ़ाना और सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना एवं खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना
- केंद्र : राज्य = 60: 40

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - सूक्ष्म सिंचाई (PMKSY-MI)

- इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है।
- केंद्र : राज्य = 60:40
- भारत सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।

1 राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (NMAET) 2014

- **उद्देश्य:**
  - कृषकों की सक्रिय भागीदारी के साथ 'रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना बनाना।
  - संसाधनों के आवंटन में ब्लॉक स्तर पर सभी हितधारकों के बीच कार्यक्रम समन्वय और एकीकरण को बढ़ाना।
  - केंद्र : राज्य = 60: 40
- इसमें 3 उप-मिशन शामिल हैं-
  - कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE)
  - बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP)
  - कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)

2 राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) 2014

- **केंद्र :** राज्य = 60 : 40
- **NMSA के तीन उप-मिशन:-**

अ. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)।

ब. मृदा स्वास्थ्य कार्ड:- प्रारंभ - 19 फरवरी, 2015 सूरतगढ़ (गंगानगर) से

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस- 19 फरवरी
- **उद्देश्य:**
  - मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना।
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
  - विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन।
- राज्य के सभी 352 ब्लॉकों में प्रभावी।

स. कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF):-

प्रारंभ - 2017-18

- उद्देश्य: वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।

D. परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):

- जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन किया जाता है।

3 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):-

- **प्रारंभ -** वर्ष 2007-08
- **केंद्र :** राज्य = 60: 40
- **उद्देश्य:**
- कृषि में निवेश को बढ़ावा देना।
- कृषि में 4% विकास दर सुनिश्चित करना।

4 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM):- (2005)

- राजस्थान के 24 जिलों में कार्यान्वित।
- फलों, मसालों और फूलों का क्षेत्रफल तथा उत्पादन बढ़ाना।

5 सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना [प्रधानमंत्री 'कुसुम' योजना घटक 'बी']

- पीएम 'कुसुम' (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान)
- **प्रारंभ-** फरवरी 2019 में
- **मंत्रालय:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,भारत सरकार
- योजनान्तर्गत 3 घटकों के तहत वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावॉट अतिरिक्त सौर क्षमता हासिल की जाएगी।
- **पहला सौर ऊर्जा संयंत्र** - भालोजी गांव (कोटपुतली)
- **प्रावधान:** 3 HP से 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की स्थापना।
- **इस योजना के तहत -**